मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.2697

06.03.2020 को उत्तर के लिए

वनक्षेत्र का पुनर्विकास

2697. श्री नंदकुमार सिंह चौहान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देशभर में वनक्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए किसी समिति का गठन करने या कोई कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गठित समिति/कार्यक्रम की सिफारिशों के परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वनों के पुनर्विकास में स्वैच्छिक संगठनों और निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ) देश में वन क्षेत्रों के पुनर्विकास और पुनर्स्थापन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दो प्रमुख वनीकरण योजनाओं नामत: अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और भूदृश्य आधार पर वृक्षारोपण के लिए ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम), को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/पारि-विकास समितियों की सहभागिता से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनमें स्थानीय ग्रामवासियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। जीआईएम को ग्राम पंचायतों, ग्राम सभा और ग्राम स्तर पर उनके द्वारा गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर की समितियों/रेजीडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशनों को नगर निगमों और नगरपालिकाओं से लिंक किया गया है।

वृक्षारोपण/वनीकरण के कार्य, भारत सरकार की विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे वनेतर सरकारी और निजी भूमि पर राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि भूमि पर संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अधीन कृषि वानिकी पर उप-मिशन आदि के तहत भी किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य योजना/गैर-योजना स्कीमों के तहत और अनेक विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटियों, कार्पोरेट निकायों आदि द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है।

विभिन्न वनीकरण उपायों के कार्यान्वयन और विभिन्न एजेंसियों के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप वन और वृक्षावरण की बढ़ती प्रवृत्ति को बनाए रखा गया है। हाल ही में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 से स्पष्ट होता है कि आईएसएफआर 2017 की तुलना में देश में वन और वृक्षावरण के क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

****